गुजरात सरकार को पक्षकार राज्यों से देय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश	295.85 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	35.24 करोड़ रुपए
राजस्थान	132.17 करोड़ रुपए
कुल	463.26 करोड़ रुपए

(ग) गुजरात सरकार को अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को अंशलागत के भुगतान संबंधी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया गया है और गुजरात सरकार की बकाया देयों का तत्काल निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को अवगत कर दिया गया है । इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति में भी विचार किया गया है जहां बकाया वाले राज्य गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के जरिए मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हुए हैं ।

बिहार में नहरों का निर्माण

6695. **श्री आरू मोहम्मद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में नहरें बनाने की कोई योजना बनाई है और नहरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय स्तर पर कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और गत दो वर्षों के दौरान सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) इस समय, बिहार में 19 वृहद और 29 मझौली सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें नहरों का निर्माण भी शामिल है । एक वृहद परियोजना नामश: सुवर्णरेखा बहु प्रयोजनी परियोजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से 1989 तक किया जा रहा था । वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है ।

(ख) और (ग) निर्माणाधीन परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं । विश्व बैंक की सहायता से चल रही राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत हयुवा ब्रांच नहर एवं डुमेरी ब्रांच नहर के नवीकरण और सुवर्णरेखा परियोजना के चरण–II के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 1993–94 और 1994–95 के दौरान क्रमश: 357.49 लाख रुपए और 166.27 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की गयी । इसके अतिरिक्त डॉन ब्रांच नहर के नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के रूप में 173 लाख रुपए नियुक्त किए गए ।

Agreement between India and Nepal on Tanakpur Hydel Project

6696. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have agreed to examine the proposals made by Nepal on the issue of Tanakpur Hydel Project; and

(b) if go, the details (hereof?